डायमॉन्ड प्लास्टिक उद्योग ईटीसी।

बनाम

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य.

9 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

बीमार उद्योग-राज्य सरकार द्वारा लिया गया-बी. आई. एफ. आर. का निर्णय भुगतान के संबंध में-पक्षों पर बंधन-पक्ष को लंबित भुगतान-राज्य सरकार ने बी. आई. एफ. आर. द्वारा जारी निर्देश को लागू करने का निर्देश दिया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 3629\1997

डब्ल्यू. ए. सं. 16293/1992 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांकित 23-04-1994।

नरसिम्हा पी. एस. रीना एन. और वी. जी. परागसम Appellants.

A.T.M. संपत, वाई. पी. राव और टी. अनिल Kr. for प्रत्यर्थियों के लिए

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दे दी गई।

इन मामलों का निपटारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सहायक विकास कार्यक्रम के प्रवर्तकों के लिए संशोधित और अद्यतन दिशानिर्देशों को अपनाते समय उद्यम, दिनांक 3 अक्टूबर, 1979 की कार्यवाही द्वारा, हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम रहा है, ने आवश्यक की आपूर्ति के लिए विभिन्न सहायक उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, अपीलकर्ताओं ने घड़ी बक्से, घड़ी पट्टियों और डायल होल्डिंग की आपूर्ति के लिए सहायक इकाई स्थापित की है । जो राशि के भुगतान के संबंध में एक विवाद था । उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी । विद्वान एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 19 जनवरी 1998 मैं यह निर्देशि ा जसमें सरकार को संयंत्र स्तर समिति नियुक्त करने और उसके तहत जारी किए गए लागू करने योग्य दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था; सहायक उद्योग आने वाली इकाइयाँ हैं। योजना के भीतर; और इसलिए, पादप स्तर की सिफारिशें इस आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने 15 मार्च, 1991 के अपने आदेश द्वारा एक रिट दायर की जिसमें यह कहा गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कि एच. ए. एल. को एकल आई. डी. 2 द्वारा जारी निर्देश का पालन करने के लिए राज्य सरकार को आदेश जारी करने के बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि डी. एच. आर. की कीमतें 5.81 रुपये से घटाकर 2.48 रुपये कर दी गई

थीं, अपीलकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और तर्क दिया कि में कमी इस विवाद में नहीं है कि बाद में एच. ए. एल. के बीमार उद्योग बनने के बाद से यह मामला बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ।

M/s.Voltas लिमिटेड में चला गया है, वॉच मैन्यूफैक्चर-सी ट्यूरिंग डिवीजन को छोड़कर सभी इकाइयों के अधिग्रहण के बाद काम करना शुरू कर दिया है, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और liabilities. बी. आई. एफ. आर. का निर्णय पार्टियां को बाध्य करता है, सूचित किया जाता है कि Rs.27 लाख पहले ही अपीलआंट को भुगतान कर दिए गए हैं, जो भी देयता हो, बी. आई. एफ. आर. के समक्ष वचन के अनुसार शेष राशि का दावा कर रहे हैं, जो पक्षों को बाध्य करता है; डी. राज्य सरकार बी. आई. एफ. आर. द्वारा जारी निर्देश को लागू करने के लिए भी बाध्य है।

तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। कोई व्यय् नहीं

अपीलो का निस्तारण किया जाता है

जीएन.